



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380]
No. 380]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 1985/भाद्र 4, 1907
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 1985/BHADRA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(विदेश-कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1985

आय-कर

अनुबंध

प्रतीकाल

आय के बोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत की सरकार और
जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार के बीच 18 मार्च, 1959 को
हस्ताक्षरित करार में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल ।

भारत के गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य ;

आय के बोहरे कराधान के परिहार के लिए दोनों राज्यों के बीच
18 मार्च, 1959 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार में (जिसे इसके
बाद "करार" के रूप में उल्लिखित किया गया है, संशोधन करने की
इच्छा से;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद I

करार के शीर्षक को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ
रखा जाएगा :

"आय और पूंजी पर करों के सम्बन्ध में बोहरे कराधान के परिहार
के लिए जर्मनी के संघीय गणराज्य

और

भारत के गणराज्य के बीच करार" ।

मा०का०नि० 680(अ).--आय पर करों से संबंधित बोहरे करा-
धान के परिवर्जन के लिए भारत सरकार और फेडरल रिपब्लिक
जर्मनी के बीच हुए करार का संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य
और फेडरल रिपब्लिक जर्मनी के बीच उपाबद्ध प्रोटोकॉल हुआ और इसका
अनुसमर्थन कर दिया गया है और उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 16 द्वारा
यथा अपेक्षित लिखतों का आदान-प्रदान 10 जुलाई, 1985 को कर
दिया गया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का
7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन
देती है कि उक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी
किया जाएगा ।

अनुच्छेद II

अनुच्छेद IV

करार के अनुच्छेद I के पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (क) और (ख) को हटाकर उनके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :

“(क) जर्मनी के संघीय गणराज्य में :

- (i) आयकर (आइन्कोमेन्स्ट्यूर)
- (ii) निगमकर (कीर्पर्सैसैम्स्ट्यूर)
- (iii) पूँजी कर (वर्मिगेन्सट्यूर), और
- (iv) व्यापारिक कर (जेवरबेस्ट्यूर)

(जिन्हें इसके बाद “जर्मनी कर” कहा गया है) ;

(ख) भारत में :

- (i) आयकर जिसमें आयकर पर कोई अधिभार भी शामिल है,
- (ii) अप्रिभार, और
- (iii) धनकर

(जिन्हें इसके बाद “भारतीय कर” कहा गया है) ।”

अनुच्छेद III

करार के अनुच्छेद I के बाद निम्नलिखित पाठ के साथ एक तथा अनुच्छेद 1क जोड़ दिया जाएगा :

“(1) इस करार के प्रयोजनों के लिए, “संविदाकारी राज्य का निवासी” पद से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर उस राज्य के कानूनों, के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-व्यवस्था के स्थान अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के कारण वहाँ कर लगाया जा सकता है।

(2) जहाँ पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसको हैमियत नीचे निम्ने नियमों के अनुसार तय की जाएगी :

- (क) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका स्थायी घर हो । यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी घर है तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक सम्बन्ध अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ हों (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
- (ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निश्चित नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसको दोनों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- (ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में आदतन नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक न हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

(3) जहाँ पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के कारण, किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसको प्रभावी प्रबन्ध-व्यवस्था का स्थान स्थित है ।

(1) करार के अनुच्छेद II के पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (क), (ख) तथा (ग) को हटाकर उनके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :

“(क) “संघीय गणराज्य” पद से अभिप्रेत है जर्मनी का संघीय गणराज्य और भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त किये जाने पर ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसमें जर्मनी के संघीय गणराज्य के कर कानून लागू होते हैं ;

(ख) “भारत” पद से अभिप्रेत है भारत का गणराज्य और भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त किये जाने पर ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसमें भारत के गणराज्य के कर कानून लागू होते हैं ;

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” और “दूसरा संविदाकारी राज्य” शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार संघीय गणराज्य अथवा भारत अभिप्रेत है ।”

(2) करार के अनुच्छेद II के पैराग्राफ (I) के उप-पैराग्राफ (ख) को हटा दिया जाएगा तथा उप-पैराग्राफ (ज), (झ), (ञ), (ट) तथा (ठ) को क्रमशः (छ), (ज), (झ), (ञ) और (ट) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

(3) पैराग्राफ (2) द्वारा यथा पुनः संख्यांकित, करार के अनुच्छेद II के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ज) को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :

“(ज) (कक) “स्थायी संस्थापन” पद का अर्थ है कारोबार का वह निश्चित स्थान जिसके जरिये किसी उद्यम वा कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

(खख) “स्थायी संस्थापन” पद में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) प्रबन्ध व्यवस्था का स्थान ;
- (ii) शाखा ;
- (iii) कार्यालय ;
- (iv) कारखाना ;
- (v) कार्यशाला ;
- (vi) बिक्री का स्थान ;
- (vii) मातृगोशाला ; और
- (viii) खान, तेल अथवा गैस कूप, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई भी अन्य स्थान ।

(गग) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण अथवा संस्थापन परियोजना, स्थायी संस्थापन तभी होती है जब वह छः महीने से अधिक समय तक रहती है ।

(घघ) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होने हुए भी, “स्थायी संस्थापन” में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (i) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ii) उद्यम के माल अथवा पण्यों के स्टॉक को केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रखना ;
- (iii) अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टॉक रखना ;
- (iv) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों को केवल श्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत स्थान बनाये रखना ;

(v) उद्यम के लिये, केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म का कोई भी अन्य कार्यकलाप करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत स्थान बनाये रखना;

(vi) उप-पैराग्राफ (i) से (v) तक में उल्लिखित कार्य कलापों के केवल किसी संयोजन के लिए कारोबार का कोई नियत स्थान बनाये रखना बणर्त कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के नियत स्थान का समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म का हो।

(क) हमारे संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति, जो स्वतन्त्र शैलियत के कियो ऐमें अधिकारी से भिन्न हो जिस पर उप-पैराग्राफ (च) लागू होता हो, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जायगा।

(i) यदि उसे आमतौर से उस संविदाकारी राज्य में उस उद्यम के नाम से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आमतौर से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसकी शक्तिविधियां उस उद्यम के लिए माल अथवा सामान खरीदने तक ही सीमित न हों; अथवा

(ii) यदि वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में आमतौर से उस उद्यम के माल अथवा निजारी माल का स्टॉक रखता हो, जिसमें से वह उस उद्यम के लिए अथवा उसकी ओर से माल अथवा निजारी माल नियमित रूप से भेजता हो; अथवा

(iii) यदि वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में, अनन्यतः अथवा लगभग अनन्यतः उद्यम के लिए हो, अथवा उस उद्यम के लिए अथवा ऐसे अन्य उद्यमों के लिये नियमित रूप से आर्डर प्राप्त करता है तो जो उसके द्वारा नियंत्रित होते हों, अथवा उनमें नियंत्रक हित रखता हो।

(च) किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए कोई स्थायी संस्थापन होता नहीं माना जाएगा कि वह किसी दशाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतन्त्र शैलियत के किसी अन्य एजेंट के माध्यम से उस राज्य में कारोबार करता है, बणर्त कि इस प्रकार के व्यक्ति सामान्यतः अपने कारोबार के दौरान ऐसा करते हों।

(छ) इस तथ्य से कि कोई कंपनी, जो किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, और हमारे संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी को नियन्त्रित करती है अथवा उसमें नियंत्रित होती है अथवा जो उस हमारे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, वे दोनों कंपनियां एक दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं बनेंगी।

(4) पैराग्राफ (2) द्वारा यथा पुनः संख्याकित, करार के अनुच्छेद II के पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (ट) के बंद निम्नलिखित तथा उप-पैराग्राफ (1) जोड़ दिया जाएगा :-

“(1) “द्वितीय वर्ष” पद का अर्थ है :

(i) भारतीय कर के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम 1961 में यथा परिभाषित पिछला वर्ष,

(ii) जर्मन कर के सम्बन्ध में, कैलेण्डर वर्ष।”

(5) इस करार में जहां कहीं “राज्य क्षेत्र”, “राज्यक्षेत्रों”, “संघीय गणराज्य कर” तथा “राज्य क्षेत्रों में से किसी एक का निवासी” शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनके स्थान पर क्रमशः “संविदाकारी राज्य”, “संविदाकारी राज्यों”, “जर्मन कर” तथा “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” शब्दों को रखा जाएगा।

अनुच्छेद V

करार के अनुच्छेद III को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :

“(1) एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि वह उद्यम हमारे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो, तो उद्यम के लाभों पर उस हमारे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उतने हो लाभों पर जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं।

(2) पैराग्राफ (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम हमारे संविदाकारी राज्य में स्थित किया स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का हो। लाभ समझा जाएगा जिसे, उसके द्वारा प्राप्त होने का तब श्रेष्ठा को जाता जब वह उन्हीं या वैसे ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के माध्यम पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

(3) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण वे उद्यमों को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र, और जिनकी स्वीकृति उस संविदाकारी राज्य के अपने आन्तरिक कानून के अनुसार का जाना है, जिस में स्थायी संस्थापन स्थित है।

(4) जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में संविभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ (2) में बताई गई कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य को, कर लगने योग्य लाभों को ऐसा यथा-शक्ति संविभाजन पद्धति द्वारा निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा; लेकिन, अपनानी गई संविभाजन पद्धति ऐसा होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(5) कोई लाभ, मात्र इस कारण स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य बस्तुएं खरीदी गई हैं।

(6) पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

(7) जहां लाभों में श्राव को वे मई शामिल हों, जिसका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।”

अनुच्छेद VI

करार का अनुच्छेद VI हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :

- “(1) अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोत संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जाएगा, जिसमें उद्यम की प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था का स्थान स्थित है।
- (2) पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, इस प्रकार के लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जहाँ से वे प्राप्त हुए हों, बशर्ते कि इस प्रकार प्रभारित कर, राज्य के आन्तरिक कानून द्वारा कन्या लगाए जाने वाले कर के,
- (क) दिनांक 28 जून, 1984 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के प्रवर्तन के पश्चात् प्रथम पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान, 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और
- (ख) उत्तरवर्ती पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तत्पश्चात् केवल पैराग्राफ (1) के उपबन्ध लागू होंगे।
- (3) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध किसी पूल सेवा, किसी सीधे कारोबार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय यातायात एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।
- (4) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध तटवर्ती यातायात के परिणामतः उत्पन्न लाभों पर लागू नहीं होंगे। “तटवर्ती यातायात” पद से ऐसा यातायात अभिप्रेत है, जो कि उसी संविदाकारी राज्य के राजकोषीय समुद्र में प्रारम्भ और समाप्त हो।”

अनुच्छेद VII

करार का अनुच्छेद VII हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :

- “(1) जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को अदा किये गये लाभांश, उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।
- (2) लेकिन, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे, जिसकी लाभांश अदा करने वाला कंपनी निवासी है, और यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जाएगा। किन्तु, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :
- (क) संघीय गणराज्य के मामले में लाभांशों का सकल रकम का 15 प्रतिशत ;
- (ख) भारत के मामले में, जहाँ लाभांश पूर्णतः अथवा अंशतः नये अंशदान से सम्बन्धित होते हैं, नये अंशदान के कारण होने वाले लाभांशों का सकल राशि का 15 प्रतिशत।

इस अनुच्छेद में प्रयुक्त “नया अंशदान” पद से, किसी ऐसे कंपनी द्वारा जो भारत की निवासी है तथा संघीय गणराज्य के किसी निवासी के हितभागी स्वामित्व में है, दिनांक 28 जून, 1984 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के प्रवर्तन की तारीख के पश्चात् जारी किये गये बोनस शेयरों में बिना कोई भी शेयर पूर्ण अभिप्रेत है।

- (3) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “लाभांशों” पद का अभिप्राय लाभों में अंशधारि शेयरों, माइनिंग शेयरों, संस्थापक शेयरों तथा अन्य अधिकारों जो ऋण दावे नहीं हैं, से प्राप्त आय, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त ऐसी आय से भी

है जिस पर उस राज्य के जितनी वितरण करने वाले कंपनी निवासी हैं, कानून द्वारा, उसी प्रकार कर लगाया जाता है जिस प्रकार शेयरों से प्राप्त आय पर, तथा किसी निष्क्रिय भागीदार द्वारा इस प्रकार भाग लेने पर प्राप्त आय तथा किसी निवेशाग्न्यास के सट्टिकेडों पर वितरित रकमों से है।

- (4) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से, जिसकी लाभांश अदा करने वाला कंपनी निवासी है, कारबार करता है और जिस धारिता के बारे में लाभांशों का अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद III के उपबन्ध लागू होंगे।
- (5) जहाँ कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ कंपनी द्वारा दिये गये लाभांशों पर, जहाँ तक कि ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो कि उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किये गये हों अथवा जिस धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है, उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ कर का किसम का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किये गये लाभांश अथवा अवितरित लाभों में पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय ही क्यों न हो।”

अनुच्छेद VIII

करार का अनुच्छेद VIII हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :

- “(1) एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को अदा किये जाने वाले ध्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।
- (2) तथापि, इस प्रकार के ध्याज पर भा उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है। किन्तु यदि दिनांक 28 जून, 1984 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के प्रवर्तन की तिथि के पश्चात् दिये गये ऋण अथवा ऋण 100 ऋण के सम्बन्ध में देय ध्याज पर इस प्रकार प्रभावी कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :
- (क) सकल राशि का 10 प्रतिशत यदि इस प्रकार का ध्याज बैंक द्वारा मंजूर किये गये किसी भी प्रकार के किस भी ऋण पर संदर्भ किया जाता है, और
- (ख) अन्य सभी मामलों में सकल राशि का 15 प्रतिशत।
- (3) पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी,
- (क) संघीय गणराज्य में उद्भूत होने वाले और भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को अदा किये गये ध्याज को जर्मन कर से छूट प्राप्त होगा।
- (ख) भारत में उद्भूत होने वाले और जर्मनी के संघीय गणराज्य, दि ह्यूम्बोल्ट बंदीस बैंक, दा केडिटेंस्टाल फर कोइरोफे या दा ड्यूशान्गेमेनफाफ्ट कर विद्वसफाफ्टफिने जुगुमेनरबैट (इन्टर्नल लीजसेल फाफ्ट) को अदा किये गये ध्याज को भारतीय कर से छूट प्राप्त होगा।

- (4) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'व्याज' शब्द से हर प्रकार के ऋण-पत्रों से भ्राम्य अभिप्रेत है, चाहे वे बन्धकपत्र से प्रत्याभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋणदाता के सामने, विशेषकर सरकार, प्रतिभूतियों से और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से होने वाले भ्राम्य में, जिसमें इस प्रकार के प्रतिभूतियों, बन्ध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से सम्बद्ध किन्हीं और पारितोषिक शामिल हैं, भागीदारों का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं।
- (5) व्याज, किन्हीं संविदाकारों राज्य में उस स्थिति में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब भ्रदा करने वाला स्वयं संविदाकार राज्य, कोई देश, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ व्याज भ्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकार राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकार राज्य में एक स्थायी संस्थापन है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर व्याज का भ्रदायगी कर्तव्य है और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है, तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।
- (6) पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज का हितभागी स्वामी, जो कि एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता हो और जिस ऋणदाते के बारे में ऋण भ्रदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामलों में अनुच्छेद III के उपबन्ध लागू होंगे।"

अनुच्छेद IX

करार के अनुच्छेद VIII के पश्चात् एक नया अनुच्छेद VIII क, अन्तःस्थापित किया जाएगा, जिसका पाठ निम्नानुसार होगा :

- "(1) एक संविदाकार राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकार राज्य के निवासी को, अथवा कोई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- (2) लेकिन, इस प्रकार के रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकार राज्य में भ्र कर लग सकेगा, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा। परन्तु, जहाँ तक तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का सम्बन्ध है, इस प्रकार लगाया गया कर, इस प्रकार के फीस के सकल राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (3) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त 'रायल्टियाँ' शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, जिनमें, चलचित्र फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्मों अथवा टेपें भी शामिल हैं, का कोई कापी राइट, कोई पेटेंट, व्यापार चिन्ह, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किन्हीं भी प्रकार का भ्रदायगी अभिप्रेत है।
- (4) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से प्रवन्धक, तकनीकी अथवा परामर्शदाता स्वयं

का सेवाओं के, जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कामियों की सेवाओं का व्यवस्था सम्मिलित है, प्रतिफल में भ्रदायगीयों करने वाले व्यक्ति के कर्मचारों को कर्तव्य भ्रदायगीयों से भिन्न किन्हीं भी व्यक्ति को का गवा किन्हीं भी प्रकार का भ्रदायगीयों अभिप्रेत है :

- (5) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं की फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, और उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होते हैं, वहाँ पर स्थित किन्हीं स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के सम्बन्ध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा कर्तव्य है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से कारगर रूप से सम्बद्ध है। इस प्रकार के मामलों में अनुच्छेद III के उपबन्ध लागू होंगे।

(6) रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिये फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी, जहाँ भ्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई देश, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिये फीस अथवा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में उसका एक स्थायी संस्थापन है जिसके संबंध में भ्रदायगीयों करने की जिम्मेदारी ली गई हो और उस स्थायी संस्थापन द्वारा भ्रदायगीयों की जाती हों, तब रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है।

(7) जहाँ भ्रदायगी करने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण भ्रदा की गई रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस की रकम किसी भी कारण से उस रकम से बढ़ जाती है, जो इस प्रकार के सम्बन्ध के न होने की स्थिति में अथवा-कोई नहीं होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध अन्तिम बर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में भ्रदायगीयों के अधिभाग पर इस करार के अन्य उपबन्धों का समुचित पालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लग सकेगा।"

अनुच्छेद X

(1) इस करार के अनुच्छेद X के मौजूदा पाठ को पैराग्राफ (1) के रूप में संशोधित किया जायेगा।

(2) निम्नलिखित पैराग्राफ (2) के रूप में जोड़ दिया जायेगा :

"लेकिन, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित जलपोतों अथवा वायुयानों और इस प्रकार के जलपोतों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त लाभ उस संविदाकारी राज्य में हो करारधेय होंगे, जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रवन्ध का स्थान स्थित हो।"

अनुच्छेद XI

करार के अनुच्छेद XV के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 1.5क अन्तःस्थापित किया जायेगा, जिसका पाठ निम्नानुसार होगा :

"(1) अनुच्छेद IX में उल्लिखित अजल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्व में हो और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

- (2) चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर, जो किसी ऐसे स्थायी संस्थापन के कारबार की सम्पत्ति का एक भाग हो, जो किसी संविदाकारी राज्य का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
- (3) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलपोतों अथवा वायुयानों और इस प्रकार के जलपोतों और वायुयानों के संचालन से सम्बन्धित इस चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित हो।
- (4) किसी कंपनी में शेयरों द्वारा निरूपित पूंजी पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिनमें कंपनी निवासी है।
- (5) किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के अन्य सभी भटकों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद XII

करार के अनुच्छेद XVI के पैराग्राफ (2) और (3) को हटा दिया जायेगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जायेगा :

“(2) जहाँ, भारत का कोई निवासी कोई आय प्राप्त करता है अथवा ऐसी पूंजी का स्वामी है, जिस पर इस करार के उपबन्धों के अनुसार संघीय गणराज्य में कर लग सकेगा, उस निवासी की आय पर भारत, संघीय गणराज्य में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अदा किये गये पूंजी-कर के बराबर की राशि; और उस निवासी की पूंजी पर कर से कटौती के रूप में, संघीय गणराज्य में अदा किये गये पूंजी-कर के बराबर की राशि, कटौती के रूप में अनुज्ञात करेगा। लेकिन, इस प्रकार की कटौती, दोनों ही मामलों में, (कटौती विये जाने से पूर्व यथा संगणित) आयकर अथवा पूंजी कर के उस लाभ से अधिक नहीं होगी, जो उस आय अथवा पूंजी, जैसा भी मामला हो, के कारण हुआ माना जा सकता है जिस पर कि संघीय गणराज्य में कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ इस प्रकार का निवासी एक कंपनी है, जिसके द्वारा भारत में अतिकर अदा करने योग्य हो, वहाँ कंपनी के द्वारा जर्मनी के संघीय-गणराज्य में अदा किए गये आयकर में कटौती प्रयोज्य। भारत में कंपनी द्वारा अदा किये जाने योग्य आयकर पर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, भारत में उसके द्वारा अदा किये जाने योग्य अतिकर पर दी जायेगी।

- (3) उपर्युक्त पैराग्राफ (1) की शर्तों के अधीन रहते हुए, संघीय गणराज्य के निवासी के मामले में कर का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :

(क) जब तक उप-पैराग्राफ (ख) के उपबन्ध लागू नहीं होते तब तक उस आधार से, जिस पर जर्मन कर लगाया जाता है, भारत में उत्पन्न होने वाली आय की किसी भी मद को तथा भारत में स्थित पूंजी की किसी भी मद को, अलग रखा जायेगा जिस पर, इस करार के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकेगा। तथापि, संघीय गणराज्य अपने कर की दरें निर्धारित करने में, इस प्रकार शामिल नहीं की गई आय तथा पूंजी की मदों को हिसाब में लेने का अधिकार रखता है।

लाभांशों से आय के मामले में, पूर्वोक्त उपबन्ध केवल उन्हीं लाभांशों पर लागू होंगे जो संघीय गणराज्य की निवासी कंपनी (जिसमें हाइब्रिड की कंपनी शामिल नहीं है) को भारत की उस निवासी कंपनी द्वारा अदा किये जाने हैं जिसकी पूंजी के कम से कम 10 प्रतिशत पर प्रयोज्य लिखित कंपनी का प्रत्यक्ष स्वामित्व हो।

पूंजी पर करों के प्रयोजनों में किसी ऐसी शेयर धारिता को भी, जिस पर जर्मन कर लगाया जाता है, उस आधार में शामिल नहीं किया जायेगा, जिसके लाभांश शामिल नहीं किये जाते हैं अथवा यदि अदा किये जाते हैं, तो तत्काल पूर्ववर्ती धार्य के अनुसार उस आधार में शामिल नहीं किया जायेगा जिस पर जर्मन कर लगाया जाता है।

(ख) विदेश कर के लिये नाम जमा के संबंध में जर्मन कर कानून के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (क्योंकि उनमें सामान्य सिद्धांतों में परिवर्तन किये बिना समय समय पर संशोधित किया जा सकता है), जर्मन आय और भारत में उत्पन्न होने वाली आय की निम्नलिखित मदों के संबंध में अदा किया जाने योग्य निगम कर, भारत के कानूनों के अधीन और इस करार के अनुसार निम्नलिखित मदों पर अदा किये गये भारतीय कर के प्रति खाने नामों की अनुमति दी जायेगी :

(कक) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जहाजरानी परिचालन से उत्पन्न लाभ ;

(खख) लाभांश, जो उप-पैराग्राफ (क) में निरूपित नहीं किये गये हैं ;

(गग) व्याज ;

(घघ) रायल्टियां तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस।

(ग) उप-पैराग्राफ (ख) की मद (खख) से (घघ) के प्रयोजन के लिये, “भारतीय कर” पद में कोई भी ऐसी राशि शामिल हुई समझी जायेगी जो भारत के कानून तथा इस करार के अनुसार किसी भी वर्ष के लिये भारतीय कर के रूप में देय हुई होगी यदि निम्नलिखित के अधीन उस वर्ष के लिये कर से छूट अथवा कटौती भंजूर नहीं की गई हो।

(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(4), 10(4क), 10(15) (iv) तथा 80ट;

(ख) इसी प्रकार का कोई अन्य उपबन्ध जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच सहमति आवश्यक है।

यदि यह राशि इस प्रकार की आय पर लगाये जाने वाले जर्मन कर के 50 प्रतिशत से कम हो, तो “भारतीय कर” पद का अर्थ जर्मन कर की कम से कम इस 50 प्रतिशत की राशि से लगा लिया जायेगा।

(घ) उप-पैराग्राफ (क) के उपबन्ध किसी ऐसी चल अथवा अचल सम्पत्ति, जो किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के अंश के रूप में हो, के लाभों को तथा उसकी प्रतीक रूप पूंजी को तथा इस प्रकार की संपत्ति के अपवर्तन से होने वाले लाभों को किसी कंपनी द्वारा अदा किये गये लाभांशों के तथा उसकी शेयर धारिता के संबंध में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक संघीय गणराज्य का संबंधित निवासी यह सिद्ध नहीं करता है कि स्थायी संस्थापन अथवा कंपनी की प्राप्ति या अन्य रूप से अथवा प्रायः अन्य रूप से प्राप्त की जाती है।

(कक) भारत में वस्तुओं अथवा माल के उत्पादन अथवा बिक्री, तकनीकी सलाह देने अथवा इंजीनियरी सेवाएँ प्रदान करने अथवा बैंकिंग या जमा व्यापार करने से प्राप्त हुई हैं, अथवा

(खख) भारत का निवासी होने के लिये एक अथवा एक से अधिक कंपनियों द्वारा अदा किये गये लाभांशों से जिसकी पूंजी का 25 प्रतिशत से अधिक भाग

प्रथमोपलब्धित कम्पनी के स्थापित्व में है, जो स्वयं भारत में अपनी प्राप्तिगत अथवा प्राप्त, अनन्यतः भारत में उत्पन्न अथवा भारत के उत्पादन या विकास, तकनीकी सहाय्य देने अथवा इंजीनियरी सेवा प्रदान करने अथवा बैंकिंग एवं बीमा कारोबार से प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार के मामले में उपर्युक्त आम तथा पूर्ण की मदीं पर, भारतीय कानून के अन्तर्गत तथा इस करार के अनुसार देय भारतीय कर को विदेशी कर के लिये खाते जमा के संबंध में जर्मन कर कानून के उपबन्धों के अधीन रखते हुए (क्योंकि उसे सामान्य सिद्धांतों में परिवर्तन किये बिना समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) जर्मन आय अथवा आय की इस प्रकार की मदीं पर देय निगम कर के प्रति अथवा इस प्रकार की पूर्ण की मदीं पर देय जर्मन कर के प्रति खाते जमा किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 13

करार के अनुच्छेद 18 को हटा दिया जाये तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रख दिया जाये :

“(1) जहाँ कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जायेगा वह इस करार के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के आन्तरिक कानूनों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवास है। मामले की उस कार्यवाही की प्रथम अधिमूचना के तीन वर्ष के अन्तर-अन्तर प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कर लगाया गया है जो करार के उपबन्धों के अनुसार नहीं है।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारियों को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी मंतोषजनक समाधान पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह हमारे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों की परम्पर सहमति में उस मामले की हल करने का प्रयास करेगा जिसमें उस कराधान का परिहार किय जा सके जो हम करार के अनुसार नहीं है। जो भी समझौता किया जायेगा उसे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानून में किसी भी समय संशोधित करने के लिये लागू कर दिया जायेगा।

(3) इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा शक्य उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों उन्हें परम्पर सहमति में हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिये परम्पर परामर्श भी कर सकते हैं जिसकी इस करार में व्यवस्था नहीं है।

(4) पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अधिप्रायः के लिये सहमति के प्रयोजनार्थ, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

अनुच्छेद XIV

यह प्रोटोकॉल बर्लिन भूमि पर भी लागू होगा बशर्ते कि इस प्रोटोकॉल के प्रवर्तन की तारीख से तीन महीने के अन्तर-अन्तर जर्मन की संघीय गणराज्य की सरकार भारत सरकार को कोई विपरीत घोषणा नहीं करती है।

अनुच्छेद

करार के अनुच्छेद XXI के उप-पैराग्राफ (क) को हटा दिया जाएगा उसके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जायेगा :

“(क) भारतीय कर के संबंध में जिस वर्ष में करार की समाप्ति करने का नोटिस किया जाता है, उस वर्ष के बाद वाले फ़रवरी वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् भारत होने वाले कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य पूर्ण तथा आय से संबंधित है, तथा”

अनुच्छेद XVI

(1) इस प्रोटोकॉल की अभिवृष्टि की जाएगी और अभिवृष्टि के दस्तावेजों का नई दिल्ली में यथा संभव भीष्म आदान-प्रदान किया जाएगा।

(2) यह प्रोटोकॉल, अभिवृष्टि के दस्तावेजों के आदान-प्रदान के एक माह बाद प्रवर्तित होगा और इसका

(क) संबंधी गणराज्य में :

(i) जनवरी 1984 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् प्रतिवासियों को भ्रम की गयी अथवा उनके खाते जमा की गयी रकमों पर खोत पर रोके गये कर के सम्बन्ध में; तथा

(ii) जनवरी 1984 के प्रथम दिन अथवा इसके पश्चात् भारत होने वाले कराधान वर्षों के लिए अन्य जर्मन कर के सम्बन्ध में;

(ख) भारत में अप्रैल 1984 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् भारत होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय तथा पूर्ण के संबंध में; प्रभाव पड़ेगा।

अनुच्छेद XVII

(1) यह प्रोटोकॉल करार का एक अभिन्न अंग होगा तथा यह सब तक लागू होता रहेगा जब तक करार प्रभावी रहेगा।

(2) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों, इस प्रोटोकॉल द्वारा यथासंशोधित, करार के मूल पाठ को इस प्रोटोकॉल के प्रवर्तन के पश्चात् प्रकाशित कर सकते हैं।

बोन में वर्ष 1984 के जून मास के 28 दिन को, अंग्रेजी, जर्मन तथा हिन्दी भाषाओं में, दो-दो प्रतियाँ में सम्पन्न किया गया, तथा इसके सभी पाठ समानतः प्रमाणिक होंगे। किसी भी मामले में अग्र' निरूपण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत के गणराज्य

जर्मनी के संघीय

की ओर से

गणराज्य की ओर से

टिप्पणियों का आदान-प्रदान

बोन, 28 जून, 1984

प्रिय महोदय,

मुझे आपका आज का पत्र स्वीकार करने का गौरव प्राप्त हुआ जो कि निम्नलिखित है :

“आज हस्ताक्षर किये गये प्रोटोकॉल के संबंध में, जिसके द्वारा जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार तथा भारत की सरकार के बीच आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए नई दिल्ली में 18 मार्च, 1959

को हस्तक्षरित करार को संशोधित किया गया है, मुझे जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार की ओर से आपको यह सूचित करना है कि दोनों संबिदाकारी राज्य निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं:—

1. करार के अनुच्छेद VII तथा VIII के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संबिदाकारी राज्य में उद्भूत व्याज तथा लाभांशों पर उस राज्य के कानून के अनुसार उसी राज्य में कर लगाया जाएगा;

(क) यदि वे ऐसे अधिकारों अथवा ऋण-दायों से प्राप्त होते हैं जो लाभों में (जिसमें किसी निष्क्रिय भागीदार द्वारा इस प्रकार अपनी सहभागिता से प्राप्त आय शामिल है, तथा संघीय गणराज्य के मामले में "पार्टीयासीज दर भेहेन" तथा "गेरीनोव्लिंगेनेन", से प्राप्त होते हैं) सहभागी होने का अधिकार रखते हैं; और

(ख) इस शर्त के अधीन इस प्रकार की आय के कर्जदार के लाभों को निर्धारित करने में वे कटौती पाने योग्य हैं।
2. जहाँ कोई कम्पनी संघीय गणराज्य की निवासी होने के कारण भारत में स्रोतों से उद्भूत आय का वितरण करती है, वहाँ करार के अनुच्छेद XVII के पैराग्राफ (3) का उप-पैराग्राफ (क), इस प्रकार वितरणों पर निगम कर के क्षतिपूर्क अधि-रोपण को जर्मन कर कानून के उन उपबन्धों के अनुसार प्रति-बाधित नहीं करेंगे, जो शेयर धारक द्वारा देय आयकर के प्रति आधारभूत कर को नामे जमा करने के लिये बनाये गये हैं।
3. करार के अनुच्छेद III के पैराग्राफ (3) के उपबन्धों के होते हुए भी, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके किसी भी अन्य कार्यालय को (वास्तविक व्यय की प्रति-पूति से अन्यथा) निम्नलिखित के रूप में भ्रष्टा की गयी अथवा प्रभावित रकमों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जायगी।

(क) रायल्टियाँ, फीस अथवा पेटेंट या इसी प्रकार के अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले भ्रदायगियाँ;

(ख) की गई विशिष्ट सेवाओं के लिये अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन; तथा

(ग) बैंकिंग संस्थाओं के मामले के प्रतिरिक्त स्थायी संस्थापन को उधार दी गई रकमों पर व्याज।
4. यह मालूम हुआ है कि करार के अनुच्छेद III के पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित प्रधान कार्यालय के खचों के संबंध में कटौतियाँ किसी भी स्थिति में उन खचों से कम की नहीं होंगी जो इस प्रोटोकॉल के प्रवर्तन की तारीख को भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य होंगी।
5. यह मालूम हुआ है कि रायल्टी की आय पर भी जानकारी प्रलेखन, जिज्ञांकन अथवा किसी भी पेटेंट, आविष्कार, माडल डिजाइन, मुद्रा कार्मुला अथवा प्रक्रिया अथवा वातावरण-विशुद्ध अथवा इसी प्रकार की परिसम्पत्ति को अथवा उनके सम्बन्ध में भारत से बाहर सूचना भेजने के लिए एकमुश्त रकम के रूप में होती है, लगने वाला कर इस प्रकार की भ्रदायगियों की सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
6. यह भी मालूम हुआ है कि करार के अनुच्छेद XVII के सम्बन्ध में "सूचना" पत्र में वस्तावेज शामिल होंगे। यह भी मालूम हुआ है कि जर्मन कर कानून में क्षतिपय शर्तों के अधीन—निवेदन करने पर—सूचना भेजने की व्यवस्था है और उक्त अनुच्छेद के होते हुए भी इन उपबन्धों के अधीन भारत में सशम प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत करना संभव हो सकेगा।

यदि आप उपर्युक्त से सहमत होने की पुष्टि करें तो मैं आपका आभासी होंडंगा, उस स्थिति में, यह टिप्पणी और इसके सम्बन्ध में आपका उत्तर इस प्रोटोकॉल का एक भाग समझा जाएगा।

श्रीमान राजदूत मेरी परम आदर भावना का आभवांसन स्वीकार करें। परमश्रेष्ठ,

श्रीमान् प्रार. डी. साडे,
भारतीय राजदूत,
बोन।

टिप्पणियों का प्रादान-प्रदान

बोन 28 जून, 1984

श्रीमान राज्य सचिव,

मुझे आपका आज का पत्र स्वीकार करने का सीमाय प्राप्त हुआ जो कि निम्नलिखित है:

"आज हस्ताक्षर किये गये प्रोटोकॉल के संदर्भ में, जिसके द्वारा जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार तथा भारत की सरकार के बीच आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए नई दिल्ली में 18 मार्च, 1959 को हस्ताक्षरित, करार को संशोधित किया गया है, मुझे जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार की ओर से आपको यह सूचित करना है कि दोनों संबिदाकारी राज्य निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं:—

1. करार के अनुच्छेद VII तथा VIII के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संबिदाकारी राज्य में उद्भूत व्याज तथा लाभांशों पर उस राज्य के अनुसार उसी राज्य में कर लगाया जाएगा,

(क) यदि वे ऐसे अधिकारों अथवा ऋण-दायों से प्राप्त होते हैं जो लाभों में (जिसमें किसी निष्क्रिय भागीदार द्वारा इस प्रकार अपनी सहभागिता से प्राप्त आय शामिल है, तथा संघीय गणराज्य के मामले में "पार्टीयासीज दर भेहेन" तथा "गेरीनोव्लिंगेनेन", से प्राप्त हैं), सह-भागी होने का अधिकार रखते हैं; और

(ख) इस शर्त के अधीन इस प्रकार की आय के कर्जदार के लाभों को निर्धारित करने में वे कटौती पाने योग्य हैं।
2. जहाँ कोई कम्पनी संघीय गणराज्य की निवासी होने के कारण भारत में स्रोतों से उद्भूत आय का वितरण करती है, वहाँ करार के अनुच्छेद XVII के पैराग्राफ (3) का उप-पैराग्राफ (क), इस प्रकार वितरणों पर निगम कर के क्षतिपूर्क अधि-रोपण को जर्मन कर कानून के उन उपबन्धों के अनुसार प्रतिबाधित नहीं करेंगे, जो शेयर धारक द्वारा देय आयकर के प्रति आधारभूत कर को नामे जमा करने के लिये बनाये गये हैं।
3. करार के अनुच्छेद III के पैराग्राफ (3) के उपबन्धों के होते हुए भी, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके किसी भी अन्य कार्यालय को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूति से अन्यथा) निम्नलिखित के रूप में भ्रष्टा की गयी अथवा प्रभावित रकमों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

(क) रायल्टियाँ, फीस अथवा पेटेंट या इसी प्रकार के अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले भ्रदायगियाँ;

(ख) की गई विशिष्ट सेवाओं के लिये अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन; तथा

(ग) बैंकिंग संस्थाओं के मामले के प्रतिरिक्त स्थायी संस्थापन को उधार दी गई रकमों पर व्याज।

4. यह मालूम हुआ है कि करार के अनुच्छेद III के पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित प्रधान कार्यालय के खर्चों के संबंध में कटौतियाँ किसी भी स्थिति में उन खर्चों से कम की नहीं होंगी जो इस प्रोत्तोकॉल के उपरान्त की तारीख को भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्त होंगी।
5. यह मालूम हुआ है कि रयल्टीकी आय पर भी जानकारी प्रलेखन, वित्तिकान अथवा किसी भी पेटेंट, जाविज्जकार, माडल डिजाइन, गुप्त कर्मज्ञ, अथवा प्रक्रिया अथवा व्यापार-चिन्ह अथवा इसी प्रकार की परिसम्पत्ति को अथवा उनके सम्बन्ध में भारत से बाहर सूचना भेजने के लिए एक-मुहत्त रकम के रूप में होती है, लगने वाला कर इस प्रकार की अभावगियों का सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
6. यह भी मालूम हुआ कि करार के अनुच्छेद 17 के सम्बन्ध में, "सूचना" पद में वस्तुस्थिति शामिल होंगी। यह भी मालूम हुआ है कि जर्मन कर कानून में कतिपय शर्तों के अधीन—निवेदन करने पर—सूचना भेजने की व्यवस्था है और उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत भी इन उपबन्धों के अधीन भारत में सक्षम प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत करना सम्भव हो सकेगा।

यदि आप उपर्युक्त से सहमत होने की पुष्टि करें तो मैं आपका आभारी होऊंगा, उस स्थिति में, यह टिप्पणी और इसके सम्बन्ध में आपका उत्तर इस प्रोत्तोकॉल का एक भाग समझा जाएगा।

मुझे आपको यह सूचित करने का शीघ्र प्राप्त हुआ है कि मेरी सरकार उपर्युक्त से सहमत है।

श्रीमान् राज्य सचिव मेरी परम आदर भावना का आभ्यासन स्वीकार करें।

परमश्रेष्ठ

डॉ. आन्ड्रेयास मायर-लांडस्ट
विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव
बोन।

[फा. स. 501/2/80-वि०क०प्र० नं० 6387]

बी०यू० एरडि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1985

INCOME-TAX

G.S.R. 680(E).—Whereas the annexed Protocol between the Republic of India and the Federal Republic of Germany amending the Agreement between the Government of India and the Government of the Federal Republic of Germany for the Avoidance of Double Taxation of Income has been ratified and the instrument of ratification exchanged as required by Article XVI of the said Protocol on 10th July, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and section 24A of the Companies (Profits) 712 GI/85—2

Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

PROTOCOL

Amending the agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation of Income signed on 18 March, 1959. The Republic of India and the Federal Republic of Germany :

Desiring to amend the Agreement for the Avoidance of Double Taxation of Income signed in New Delhi on 18 March, 1959 between both States (hereinafter referred to as "The Agreement");

Have agreed as follows :

ARTICLE I

The title of the agreement shall be deleted and replaced by the following text :

"AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND
CAPITAL"

ARTICLE II

Sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (I) of Article I of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text :

"(a) in the Federal Republic of Germany :

- (i) the income tax (Einkommensteuer),
 - (ii) the corporation tax (Körperschaftsteuer),
 - (iii) the capital tax (Vermögensteuer) and
 - (iv) the trade tax (Gewerbesteuer)
- (hereinafter referred to as "German tax");

(b) in India :

- (i) the income-tax including any surcharge thereon,
 - (ii) the surtax, and
 - (iii) the wealth-tax
- (hereinafter referred to as "Indian tax").

ARTICLE III

After Article I of the Agreement, a new Article IA shall be inserted with the following text :

"(1) for the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of

his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated."

ARTICLE IV

(1) Sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) of Article II of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text :

- "(a) the term "Federal Republic" means the Federal Republic of Germany, and when used in a geographical sense, the area in which the tax law of the Federal Republic of Germany is in force ;
- (b) the term "India" means the Republic of India, and when used in a geographical sense, the area in which the tax law of the Republic of India is in force ;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Federal Republic of India, as the context requires."

(2) Sub-paragraph (g) of paragraph (1) of Article II of the Agreement shall be deleted and sub-paragraphs (h), (i), (j), (k) and (l) shall be renumbered as (g), (h), (i), (j) and (k) respectively.

(3) Sub-paragraph (h) of paragraph (1) of Article II of the Agreement, as renumbered by paragraph

(2), shall be deleted and replaced by the following text :

"(h) (aa) the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(bb) the term "permanent establishment" includes especially :

- (i) a place of management ;
- (ii) a branch ;
- (iii) an office ;
- (iv) a factory ;
- (v) a workshop ;
- (vi) a sales outlet ;
- (vii) a warehouse ; and

(viii) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

(cc) A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

(dd) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (i) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (ii) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display ;
- (iii) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (iv) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise ;
- (v) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character ;
- (vi) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (i) to (v) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(ee) A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, other than an agent of an independent status to whom sub-paragraph (ff) applies, shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned Contracting State.

- (i) if he has, and habitually exercises in that Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise ; or
 - (ii) if he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise ; or
 - (iii) if he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State exclusively, or almost exclusively, for the enterprise itself, or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.
- (ff) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
- (gg) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other ;”

(4) After sub-paragraph (k) of paragraph (1) of Article II of the Agreement, as renumbered by paragraph (2), the following new sub-paragraph (1) shall be added :

“(1) the term “fiscal year” means :

- (i) in relation to Indian tax, the previous year as defined in the Income-tax Act, 1961 ;
- (ii) in relation to German tax, the calendar year.”

(5) The terms “territory”, “territories”, “Federal Republic tax” and “resident of one of the territories”, wherever appearing in the Agreement, shall be replaced by the terms “Contracting State”, “Contracting States”, “German tax” and “resident of a Contracting State” respectively.”

ARTICLE V

Article III of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text :

- “(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

- (2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- (3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, and according to the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- (4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary ; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
- (5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- (6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- (7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.”

ARTICLE VI

Article VI of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text :

- “(1) Profits derived from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), such profits may be taxed in the other Contracting State from which they are derived provided that the tax so charged shall not exceed :

- (a) during the first five fiscal years after the entry into force of the Protocol signed on June 28, 1984,
50 per cent, and
- (b) during the subsequent five fiscal years,
25 per cent,

of the tax otherwise imposed by the internal law of that State. Subsequently, only the provisions of paragraph (1) shall be applicable.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

(4) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic. The term "coastal traffic" means traffic which originates and terminates in the territorial waters of the same Contracting State."

ARTICLE VII

Article VII of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text :

- "(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- (2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State. But if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed :
 - (a) in the case of the Federal Republic, 15 per cent of the gross amount of the dividends;
 - (b) in the case of India, where the dividends relate in whole or in part to a new contribution, 15 per cent of the gross amount of the dividends attributable to the new contribution.

In this Article, the term "new contribution" means any share capital, other than bonus shares, issued after the date of entry into force of the Protocol signed on June 28, 1984 by a company which is a resident of India, and beneficially owned by a resident of the Federal Republic.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution

is a resident, and income derived by a sleeping partner from his participation as such and distributions on certificates of an investment trust.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article III shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State."

ARTICLE VIII

Article VIII of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text :

"(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State. But the tax so charged on interest payable in respect of a loan given or debt created after the date of entry into force of the Protocol and signed on June 28, 1984 shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount, if such interest is paid on any loan of whatever kind granted by a bank, and
- (b) 15 per cent of the gross amount in all other cases.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2),

- (a) interest arising in the Federal Republic and paid to the Indian Government or the Reserve Bank of India shall be exempt from German tax;
- (b) interest arising in India and paid to the Government of the Federal Republic of Germany, the Deutsche Bundesbank, the Kreditanstalt für Wiederaufbau or the Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit (Entwicklungsgesellschaft) shall be exempt from Indian tax.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not

carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

(5) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a land, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

(6) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article III shall apply."

ARTICLE IX

After Article VIII of the Agreement a new Article VIIIA shall be inserted with the following text:

"(1) Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State. But insofar as the fees for technical services are concerned, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of such fees.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(4) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments, in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being

a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article III shall apply.

(6) Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a Land, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to make the payments was incurred and the payments are borne by that permanent establishment, then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(7) Where, owing to a special relationship between the payer and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid exceeds for whatever reason the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement."

ARTICLE X

(1) The existing text of Article X of the Agreement shall be numbered as paragraph (1).

(2) The following shall be added as paragraph (2) :

"However, gains from the alienation of ships or aircraft operating in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated."

ARTICLE XI

After Article XV of the Agreement a new Article XVA shall be inserted with the following text :

"(1) Capital represented by immovable property referred to in Article IX, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State may be taxed in that other State.

- (3) Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- (4) Capital represented by shares in a company shall be taxable in the Contracting State in which such company is resident.
- (5) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State."

ARTICLE XII

Paragraphs (2) and (3) of Article XVI of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text :

- "(2) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Federal Republic, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income-tax paid in the Federal Republic, whether directly or by deduction ; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in the Federal Republic. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income-tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in the Federal Republic. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income-tax paid in the Federal Republic shall be allowed in the first instance from income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.
- (3) Subject to the provisions of paragraph (1) above, tax shall be determined in the case of a resident of the Federal Republic as follows :
 - (a) Unless the provisions of sub-paragraph (b) apply, there shall be excluded from the basis upon which German tax is imposed any item of income arising in India and any item of capital situated within India,

which, according to this Agreement, may be taxed in India. The Federal Republic, however, retains the right to take into account in the determination of its rate of tax the items of income and capital so excluded.

In the case of income from dividends the foregoing provisions shall apply only to such dividends as are paid to a company (not including partnerships) being a resident of the Federal Republic by a company being a resident of India at least 10 per cent of the capital of which is owned directly by the first-mentioned company. For the purposes of taxes on capital there shall also be excluded from the basis upon which German tax is imposed any shareholding, the dividends of which are excluded or, if paid, would be excluded, according to the immediately foregoing sentence, from the basis upon which German tax is imposed.

- (b) Subject to the provisions of German tax law regarding credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), there shall be allowed as a credit against German income and corporation tax payable in respect of the following items of income arising in India the Indian tax paid under the laws of India and in accordance with this Agreement on :
 - (aa) profits derived from the operation of ships in international traffic ;
 - (bb) dividends not dealt with in sub-paragraph (a) ;
 - (cc) interest ;
 - (dd) royalties and fees for technical services.
- (c) For the purpose of lt. (bb) to (dd) of sub-paragraph (b), the term "Indian tax" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Agreement for any year but for an exemption from, or reduction of, tax granted for that year under :
 - (a) sections 10(4), 10(4A), 10(15)(iv) and 80K of the Income-tax Act, 1961 ;
 - (b) any other provision of similar character to be agreed between the competent authorities of both Contracting States.

If this amount is less than 50 per cent of the German tax chargeable on such income, the term "Indian tax" shall be deemed to be at least this 50 per cent of the German tax.

(d) The provisions of sub-paragraph (a) shall not apply to the profits of, and to the capital represented by, movable and immovable property forming part of the business property of a permanent establishment and to the gains from the alienation of such property; to dividends paid by, and to the shareholding in a company unless the resident of the Federal Republic concerned proves that the receipts of the permanent establishment or company are derived exclusively or almost exclusively.

(aa) from producing or selling goods or merchandise, giving technical advice or rendering engineering services, or doing banking or insurance business, within India, or

(bb) from dividends paid by one or more companies, being residents of India, more than 25 per cent of the capital of which is owned by the first-mentioned company, which themselves derive their receipts exclusively or almost exclusively from producing or selling goods or merchandise, giving technical advice or rendering engineering services, or doing banking or insurance business, within India.

In such a case, Indian tax payable under the laws of India and in accordance with this Agreement on the above-mentioned items of income and capital shall, subject to the provisions of German tax law regarding credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), be allowed as a credit against German income or corporation tax payable on such items of income or against German capital tax payable on such items of capital."

ARTICLE XIII

Article XVIII of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text:

"(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any Agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs."

ARTICLE XIV

This Protocol shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federal Republic of Germany does not make a contrary declaration to the Government of India within three months of the date of entry into force of this Protocol.

ARTICLE XV

Sub-paragraph (a) of Article XXI of the Agreement shall be deleted and replaced by the following text:

"(a) in respect of Indian tax, in relation to income and capital assessable for the assessment years commencing on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the notice of termination is given, and"

ARTICLE XVI

(1) This Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at New Delhi as soon as possible.

(2) This Protocol shall enter into force one month after the date of exchange of the instrument of ratification and shall have effect:

(a) in the Federal Republic:

(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January, 1934; and

(ii) in respect of other German tax for taxation years beginning on or after the first day of January, 1984;

(b) in India, in respect of income and capital assessable for any assessment year commencing on or after the first day of April, 1984.

ARTICLE XVII

(1) This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall continue in force as long as the Agreement remains effective.

(2) The competent authorities of the Contracting States are authorized to publish the text of the Agreement, as modified by this Protocol, after this Protocol comes into force.

DONE at Bonn this 28th day of June, 1984 in two originals, each in the German, English and Hindi languages, all texts being authentic. In the case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Federal
Republic of German
Sd|—

For the Republic of India
Sd|—

EXCHANGE OF NOTES

State Secretary Bonn, June 28th 1984
of the Federal Foreign Office
Excellency,

With reference to the Protocol, signed today, amending the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation of Income, signed in New Delhi on 18 March, 1959, I have the honour on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany to inform you that the two Contracting States have reached agreement on the following :

1. Notwithstanding the provisions of Articles VII and VIII of the Agreement, dividends and interest arising in a Contracting State may be taxed in that State and according to the law of that State.
- (a) if they are derived from rights or debt-claims carrying a right to participate in profits (including income derived by a sleeping partner from his participation as such, and in the case of the Federal Republic from a "partiarisches Darlehen" and from "Gewinnobligationen"), and

(b) under the condition that they are deductible in the determination of profits of the debtor of such income.

2. Where a company being a resident of the Federal Republic distributes income derived from sources within India, sub-paragraph (a) of paragraph (3) of Article XVI of the Agreement shall not preclude the compensatory imposition of corporation tax on such distributions in accordance with the provisions of German tax law, designed to ensure the crediting of the underlying tax against the income-tax payable by the shareholder.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph (3) of Article III of the Agreement, no deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of—
 - (a) royalties, fees or similar payments in return for the use of patents or other similar rights;
 - (b) commission for specific services performed or for management; and
 - (c) interest on moneys lent to the permanent establishment, except in the case of a banking institution.
4. It is understood that the deductions in respect of the head office expenses as referred to in paragraph (3) of Article III of the Agreement shall in no case be less than what are allowable under the Indian Income-tax Act as on the date of entry into force of this Protocol.
5. It is understood that the taxation of royalty income as consists of lump sum consideration for the transfer outside India of, or the imparting of information outside India in respect of, any data, documentation, drawing or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property, shall not exceed 20 per cent of the gross amount of such payments.
6. It is also understood that in relation to Article XVII of the Agreement, the term "information" shall include documents. It is further understood that the German tax law provides for the transmission of information

under certain conditions—upon request—
and it would be possible to furnish information to the competent authority in India under these provisions irrespective of the said Article.

I shall be grateful if you will kindly confirm your agreement to the above; in such case, this Note and your reply thereto shall be deemed to be part of the Protocol.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Sd/-

His Excellency R. D. Sathe,
Ambassador of the Republic
of India
in the Federal Republic
of Germany,
Bonn.

EXCHANGE OF NOTES

Ambassador of India Bonn, June 28th, 1984
Bonn

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your Note of today which reads as follows :

"With reference to the Protocol, signed today, amending the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation of Income, signed in New Delhi on 18 March, 1959, I have the honour on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany to inform you that the two Contracting States have reached agreement on the following :

1. Notwithstanding the provisions of Articles VII and VIII of the Agreement, dividends and interest arising in a Contracting State may be taxed in that State and according to the law of that State,
- (a) if they are derived from rights or debt-claims carrying a right to participate in profits (including income derived by a sleeping partner from his participation as such, and in the case of the Federal Republic from a "partiarisches Darlehen" and from "Gewinnobligationen"), and

(b) under the condition that they are deductible in the determination of profits of the debtor of such income.

2. Where a company being a resident of the Federal Republic distributes income derived from sources within India, sub-paragraph (a) of Paragraph (3) of Article XVI of the Agreement shall not preclude the compensatory imposition of corporation tax on such distributions in accordance with the provisions of German tax law, designed to ensure the crediting of the underlying tax against the income-tax payable by the shareholder.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph (3) of Article III of the Agreement, no deduction shall be allowed in respect of amounts paid or charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of
 - (a) royalties, fees or similar payments in return for the use of patents or other similar rights;
 - (b) commission for specific services performed or for management, and
 - (c) interest on moneys lent to the permanent establishment, except in the case of a banking institution.
4. It is understood that the deductions in respect of the head office expenses as referred to in paragraph (3) of Article III of the Agreement shall in no case be less than what are allowable under the Indian Income-tax Act as on the date of entry into force of this Protocol.
5. It is understood that the taxation of royalty income as consists of lump sum consideration for the transfer outside India, of, or the imparting of information outside India in respect of, any data, documentation, drawing or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property, shall not exceed 20 per cent of the gross amount of such payments.

6. It is also understood that in relation to Article XVII of the Agreement, the term "information" shall include documents. It is further understood that the German tax law provides for the transmission of information under certain conditions—upon request—and it would be possible to furnish information to the competent authority in India under these provisions irrespective of the said Article.

I shall be grateful if you will kindly confirm your agreement to the above; in such case, this Note and your reply thereto shall be deemed to be part of the Protocol."

I have the honour to inform you that my Government agrees to the above.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Sd/-

(R. D. Sathe)

His Excellency
Dr. Andreas Meyer-Landrut
State Secretary
of the Federal Foreign Office
Bonn.

[F. No. 501/2/80-FTD No. 6387]

V. U. ERADI, Jt. Secy.